यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/15/2021 **दिनांक :** 06.02.2021

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

- ✓ **सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक + 2 और बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव**
- ✓ **संघर्षों और दीर्घकालीन हड़तालों के लिए तैयार रहें**

आप सभी को ज्ञात ही है कि वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में आईडीबीआई बैंक तथा 2 और बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव किया गया है। एआईबीईए द्वारा शुरू से ही बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जाता रहा है और इसके विरूद्ध विभिन्न अभियान चलाये गये हैं। पुनः खतरे को भांपते हुए एआईबीईए ने संघर्षों और दीर्घकालीन हड़तालों के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए परिपत्र संख्या 28/283/2021/7 दिनांक 5.12.2021 जारी किया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं/सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- ☐ **जैसी कि उम्मीद थी, खतरा अब दरवाजा खटखटा रहा है**
- ☐ **सरकार ने आईडीबीआई बैंक + 2 और बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव किया**
- ☐ **निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला**
- ☐ **निजीकरण का अर्थ है लोगों की बचत को निजी हाथों में सौंपना**
- ☐ **निजीकरण का अर्थ है आजीविका तथा आजीविका सुरक्षा पर हमला**
- ☐ **कठोर संघर्षों और दीर्घकालिक हड़तालों के लिए तैयार रहें**

सरकार की कथित बैंकिंग सुधार नीतियां हमारे लिए नई नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकार इन नीतियों का अनुसरण कर रही है। हम सभी जानते हैं कि ये उनकी कार्यसूची का हिस्सा हैं। यही कारण है कि हम इन उपायों के विरूद्ध अभियान चला रहे हैं और अपने सभी संघर्षों में इन्हें विशिष्ट रूप से दर्शा रहे हैं। 26 नवम्बर, 2020 की अखिल भारतीय हड़ताल में भी, हमने अपने हड़ताल के नोटिस में एक बिंदु के रूप में बैंकों के निजीकरण को मुद्दा बनाया।

इस तथ्य को कोई नहीं भूल सकता है कि उन दिनों में जब सभी बैंक निजी क्षेत्र में थे, इन बैंकों ने हमारी अर्थव्यवस्था, इसकी प्रगति और विकास के बारे में कभी चिंता नहीं की। कुप्रबंधन के कारण कई निजी बैंक ढह गए। इसलिए 1946 में आरंभ से ही, एआईबीईए ने मांग की कि भारत में बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए

जारी पृष्ठ 2

और उन्हें सरकार के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। इसलिए एआईबीईए ने दो दशकों तक संघर्ष किया और हमें गर्व है कि एआईबीईए के संघर्ष ने सरकार को 1969 में प्रमुख बैंकों का और उसके बाद 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बाध्य किया।

पिछले पांच दशकों में इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान और भूमिका अभूतपूर्व और उल्लेखनीय रही है। वे लोगों की मेहनत से अर्जित बचतों के अभिरक्षक और संरक्षक बन गए हैं। वे व्यापक आर्थिक विकास और प्रगति के इंजन बन गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारे बैंकों के चरित्र को वर्ग–बैंकिंग से सार्वजनिक–बैंकिंग में बदल दिया है। बैंकिंग आम आदमी के लिए सुलभ हो गई है।

1) ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और वृद्धि दर सुस्त है, जो आवश्यकता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और सुदृढ़ करने की है। यह एक विडबंना है कि इसके बजाय, सरकार निजीकरण करने और सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को निजी कॉर्पोरेटों को सौंपने का प्रस्ताव कर रही है, जिनमें से अधिकांश विशाल बैंक ऋणों के चूककर्ता हैं।

2) सरकार अधिक नौकरियां पैदा करने की बात करती है। लेकिन बैंकों के निजीकरण के परिणामस्वरूप स्थायी नौकरियों की कमी और अधिक से अधिक अनुबंध श्रम को रोजगार मिलेगा। एससी/एसटी, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मौजूदा आरक्षण खत्म कर दिया जायेगा क्योंकि निजी बैंकों में, आरक्षण नीति लागू नहीं है। इसलिए यह कदम कर्मचारियों के इन वर्गों की आजीविका तथा आजीविका सुरक्षा के विरूद्ध है।

3) जब कि सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि उनके पहले के सभी उपायों जैसे कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), आस्ति वसूली कंपनी (एआरसी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) ने बैंकों में उभड़े हुए खराब ऋणों को वसूल करने के लिए वांछित परिणाम नहीं दिए हैं, तो जो आवश्यकता है वो जानबूझकर चूककर्ताओं पर आपराधिक कार्रवाई करने सहित वसूली कानूनों और कानूनी प्रावधानों को कड़ा करने की है, लेकिन यह एक विडबंना है कि सरकार कॉर्पोरेट चूककर्ताओं का साथ देने के लिए बैंकों के तुलन पत्रों में लीपा–पोती के लिए खराब बैंक स्थापित करना चाहती है।

4) आईडीबीआई एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) था। सरकार ने इसे खुदरा वाणिज्यिक बैंक के रूप में बदल दिया और डीएफआई की भूमिका को छोड़ दिया गया। यह विडबंना है कि अब आईडीबीआई को निजीकृत किए जाने का प्रयास है और नया डीएफआई स्थापित करने की घोषणा की गई है।

बजट में कई अन्य प्रतिकूल, जन–विरोधी घोषणायें हैं। एलआईसी को विनिवेश के लिए निशाना बनाया गया है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी का निजीकरण करने का प्रस्ताव है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को वर्तमान 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जायेगा। इस तरह, बजट में ऐसे कई निर्णय और घोषणायें हैं।

साथियों, ऐसे क्षण आते हैं जब हमें जवाबी हमला करने के लिए खुद को योग्य साबित करने की आवश्यकता होती है। हमें पूरी तीव्रता और शक्ति के साथ जवाबी हमला करने की आवश्यकता होती है। हमारे सामने ऐसा क्षण उभर रहा है।

हमें प्रसन्नता है कि कल देशभर में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया भारी और बड़े पैमाने पर हुई है। उनका विरोध और बहिष्कार, क्रोध और झुंझलाहट, अस्वीकृति और असंतोष, आलोचना और निंदा, दिखाई दे रहे थे। हम विशेष रूप से प्रसन्नता है कि युवा कर्मचारी आगे आने वाले खतरों को महसूस करते हुए बड़ी संख्या में निकलकर आए हैं। यूएफबीयू कार्रवाई के कार्यक्रम तय करने के लिए 9 तारीख को हैदराबाद में बैठक कर रहा है। प्रतीक्षा करें। **लेकिन, तैयार रहें और मुस्तैद रहें।**

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री